(c) Till 1993-94 ITI Ltd., as a whole has been a profit making company, but during the current year, mainly due to competition, ITI Ltd., in 4 of its units viz. Rae Barei, Naini, Electronic City Unit and Bangalore in finding it difficult to get sufficient orders.

(d) With a view to remain a profit making Company as also to utilise itss infrastructure optimally, apart from upgradation of technologies, improving quality to international standards adopting various cost reduction measures and diversifying the activities to networks value added services and operating the telecom services, the Ministry has taken a policy decision that the procurement of 30 percent of equipment out of the total rquirement by DOT would be earmarked for our own P.S. Units without any concession in respect of price, quality or supply schedule.

Connecting STD Phones with Electronic Exchange in Gujarat

896. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Gujarat Telecom has a proposal to connect all STD phones with an electronic exchange;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether some other Telecom Circles are adopting the proposed to connect phones with STD facility to an electronic exchange?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) All STD phones in Gujarat Telecom Circle are proposed to be progressively connected with electronic exchanges by March, 1977.

25 Electronic exchanges planned in 1994-95 for expansion of Telephone systems were electromechanical exchanges are working at present are likely to serve STD subscribers of these electromechanical exchanges.

(c) This has been made obligatory for the Deptt. as per policy decision of the Government.

एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन बूथों के आवंटन में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दिया जाना

897. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवाओं के लिए अभिप्रेत स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एसटीडी/आईएसडी बूथों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1994 तक इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों से राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ;

(ग) सभी अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने के बाद टेलीफोन लगाने में सामान्यतः कितना समय लगता है; और

(घ) इस मामले में असाधारण विलम्ब के लिए उत्तरदायी सम्बद्ध अधिकारियों के लिए किस तरह की सजा निर्धारित है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। एस० टी डी/आईएसडी युक्त सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन किया जाता है।

(ख) 17 दूरसंचार सर्किलों/दूरसंचार जिलों के संबंध में जानकारी विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) आन्ध्र प्रदेश,

महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर पूर्वी तथा उत्तर प्रदेश, दूरसंचार सर्किलों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, एसटीडी/आईएसडी युक्त सार्वजनिक टेलीफोन लाइन के संस्थापन में आमतौर पर एक माह का समय लग जाता है, बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(घ) विभागीय नियमों के अनुसार, बिना किसी वैध कारण के निर्धारित मानदण्डों से अधिक विलंब के मामले में, विलंब के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

विवरण

सर्किल/महानगरीय जिले का नाम	अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	30.6.94 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन आवेदन-पत्र
सर्किल		
1. असम	97	13
2. बिहार	30	3
3. गुजरात	215	107
4. जम्मू तथा कश्मीर	43	शून्य
5. केरल	362	251
6. कर्नाटक	525	304
7. मध्य प्रदेश	302	138
8. उड़ीसा	31	10
9. हिमाचल प्रदेश	8	7
10. पंजाब	890	595
11. राजस्थान	146	67
12. तमिलनाडु	479	70
13. पश्चिम बंगाल	54	53
महानगरीय जिले		
1. कलकत्ता	155	39
2. मद्रास	शून्य	शून्य
3. दिल्ली	36	33
4. बम्बई	56	21